

प्रेषक,

राधिका झा  
प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा)

देहरादून दिनांक 17 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-2015 में एस0सी0एस0पी0 योजना अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, चुड़ियाला (हरिद्वार) के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डिग्री विकास/1710/2014- दिनांक 12.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय 2014-15 में एस0सी0एस0पी0 योजना अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, चुड़ियाला (हरिद्वार) के भवन निर्माण के द्वितीय चरण के कार्यों हेतु टी0ए0सी0 वित्त के परीक्षणों पर अनुमोदित धनराशि रु0 465.54 लाख की धनराशि के सापेक्ष रु0 190.16 लाख (रु0 पचास करोड़ नब्बे लाख सोलह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं। इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य कार्य नहीं किया जायेगा एवं समय-समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्ताव्ययता सम्बन्धी नियमों दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त सात दिन के भीतर सम्बन्धित निमित्त इकाई को अवमुक्त की जायेगा। भुगतान करने से पूर्व कार्यदायी संस्था से एम0ओ0 कराना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा। द्वितीय चरण के कार्य के लिए अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/xxvii(1)/20 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयवद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित हो जाय।

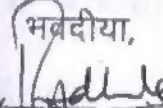
4- निदेशक उच्च शिक्षा, कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदायी संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडमिक रिव्यूअरमेंट के अनुरूप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेंगे। यदि लिखित समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदायी संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदायी संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।



.....2



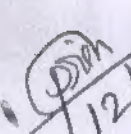
- 5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 6- उक्त निर्माण कार्य में आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर, जो भू वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार प्राविधानित किया गया है, के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा सुसंगत अभिलेखों में तकनीकी पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।
- 7- उक्त निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के एस0सी0पी0 योजना के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, लेखकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-02-चुड़ियाला (हरिद्वार) में महाविद्यालय की स्थापना/भवन निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 384(p)/xxvii(3)/2014-15 दिनांक 11 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

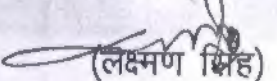
भबदीया,  
  
(राष्ट्रिय शा) प्रभारी सचिव।

पृ0सं0 3445(1)/xxiv(7)/2015-13(2)/14 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2-आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3-जिलाधिकारी हरिद्वार।
- 4-कोषाधिकारी हल्द्वानी-नैनीताल।
- 5-अधिशाली अभियन्ता उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 देहरादून।
- 6-प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय चुड़ियाला जनपद हरिद्वार।
- 7-निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय उत्तराखण्ड।
- 8-बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
- 9-वित्त अनु0-3/समाज कल्याण प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 10-गार्ड फाईल।

  
11/2/3/2015

आज्ञा से,  
  
(लक्ष्मण सिंह)  
संयुक्त सचिव।